छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 14 (अक्टूबर - दिसम्बर 2020)

ईमेलः- chhattisgarh.sccc@gmail.com वेबसाइटः- www.cgclimatechange.com

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

त्रैमासिक न्यूज़लेटर का 14 वां प्रसंस्करण जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जलवायु परिर्वतन से तात्पर्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियों के कारण जलवायु में हुए परिर्वतन से है, जो पृथ्वी के वायुमण्डल की संरचना में बदलाव करता है साथ ही प्रकृति में हुयी इस जलवायु परिर्वतनशीलता को निश्चित समय अंतराल में अवलोकन किया जा सकता है। (स्त्रोत–आई.पी.सी.सी.)

न्यूज़लेटर के इस अंक में मेरे द्वारा देश में कुछ जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों तथा जलवायु परिर्वतन के प्रभावों से निपटने हेतु भारत द्वारा की जा रही प्रमुख कार्यवाही की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है।

"Multi-Level Governance Dialogue in India Aligning Measurement, Reporting and Verification (MRV) for GHG Emission and Mitigation Actions in Chhattisgarh" का आयोजन क्लाइमेट फुटप्रिंट प्रोजेक्ट के तहत दिनांक17.12.2020 को वर्चुअल तरीके से किया गया।

इस अंक में **NAFCC** परियोजना **"Climate Adaptation in Wetlands along the Mahandi River Catchment Area in Chhattisgarh"** की नवीनतम उपलब्धियों को साझा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

इस न्यूज़लेटर के आगामी अंको को बेहतर बनाने हेतु आपकी प्रतिक्रियाओं तथा सुझावों का हम स्वागत करते हैं।

(सुधीर कुमार अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषय–वस्तु

- "Multi- Level Governance Dialogue in India Aligning Measurement, Reporting and Verification (MRV) for GHG emission and mitigation actions in Chhattisgarh" का आयोजन
- एनएएफसीसी परियोजना ''छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का क्रियान्वयन
- देश में कुछ जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियां
- देश में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किये जा रहे कुछ प्रमुख कार्य
- जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित ''इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल'' एकल बिंदु सूचना स्रोत का शुभारंभ
- जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम ने सरकार और निजी क्षेत्र के बीच दीर्घकालिक एवं टिकाऊ साझेदारी कायम की
- सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए उच्च–स्तरीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया
- समाचार शीर्षक

"Multi- Level Governance Dialogue in India Aligning Measurement, Reporting and Verification (MRV) for GHG emission and mitigation actions in Chhattisgarh" का आयोजन

क्लाईमेट फुटप्रिंट परियोजना अंतर्गत **"Multi- Level Governance Dialogue in India Aligning Measurement, Reporting and Verification (MRV) for GHG emission and mitigation actions in Chhattisgarh"** का आयोजन **ICLEI** साउथ एशिया तथा द क्लाईमेट ग्रुप के तकनीकी सहयोग से दिनांक 17.12.2020 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस आयोजन के उद्देश्य निम्नानुसार थे।

- हितधारकों (राज्य और गैर राज्य) की विस्तृत श्रृंखला को छत्तीसगढ़ में उत्सर्जन और शमन कार्यों हेतु MRV संबंधी मुद्दों के बारे में सूचित करना एवं शामिल करना।
- सभी हितधारकों का क्षेत्रीय शमन क्रियाओं, CSAPCC तथा एकीकृत MRV तंत्र के मध्य संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करना।
- शहरी स्थानीय निकायों में जलवायु कार्यवाही तथा इसकी निगरानी में होने वाली समस्याओं के विषय में बेहतर समझ बनाना।
- उत्सर्जन तथा जलवायु क्रियाओं हेतु एक सफल एकीकृत MRV प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण स्थापित करना।
- एक सफल एकीकृत MRV प्रणाली के लिए आवश्यक कार्यों की पहचान में सभी हितधारकों के सहयोग हेतु, इन कार्यों में नए अवसरों के साथ मौजूदा तंत्र और दृष्टिकोण भी शामिल करना।

इस संवाद में शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, वन, स्थानीय सरकार, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), नागरिक समाज संगठनों, वित्तीय संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को दो सत्रों में विभाजित किया गया था, पहला सत्र राज्य की जलवायु कार्यवाही तथा छ.ग. में उत्सर्जन हेतु वर्तमान MRV हेतु बाधाओं और अवरोधों को समझने पर केंद्रित था जबकि दूसरा सत्र छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरों की भूमिका पर केन्द्रित था।

प्रोफेसर एन.एच. रविन्द्रनाथ, सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साईस, बेंगलुरू सत्र के मुख्य वक्ता थे। अपने संबोधन में उन्होंने ग्रीनहाउस गैस इनवेंटोराइजेशन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने इस संबंध में केंद्र / राज्य सरकारों के लिए आवश्यक कार्रवाई की अनुसंशा की।

श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त बजट एवं कार्य आयोजना सह नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा 'Highlight of Chhattisgarh Climate Actions' विषय पर पावर प्वाईंट प्रस्तुति दी गई। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने राज्य की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना 'छत्तीगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी, के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 तथा 2020-2021 में केवल वन विभाग द्वारा कैम्पा फंड से 3700 मिलयन रूपये के 1955 विभिन्न आकारों और लंबाई के छोटे नदी / नालों के उपचार के कार्य प्रगति पर है। उन्होंने SAPCC के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रीय विभागों की उपलब्धियों का भी वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि SAPCC के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2021 तक पूर्ण हो जावेगा।

एनएएफसीसी परियोजना ''छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिर्वतन केन्द्र द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन फण्ड के अंतर्गत प्रायोजित पायलट परियोजना '' महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन '' का संचालन राज्य के तीन वनमण्डलों धमतरी, महासमुंद एवं बलौदाबाजार के 19 ग्रामों में किया जा रहा है। **NAFCC** परियोजना की समीक्षा बैठक का आयोजन नोडल अधिकारी, छ.ग.राज्य जलवायु परिर्वतन केन्द्र की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2020 को अरण्य भवन, नवा रायपुर में किया गया। परियोजना अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रूपये के विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके है। परियोजना अंतर्गत हाल ही में पूर्ण किये गये कुछ कार्यों का विवरण निम्न है :–

परकॉलेसन टैंक	40 No.
कन्टूर ट्रेंच्स के मरम्मत का कार्य	4500 No.
ग्रास सीडींग	17.706 Hec
ड्राईलैंड हार्टिकल्चर	9 No.
पुराने तालाबों के मरम्मत का कार्य	9 No.
चेक डैम	1905 Cubic Metre

एनएएफसीसी परियोजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की कुछ तस्वीरें

देश में कुछ जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियां

- 2015 के दौरान देश में अनुमानित सीवेज उत्पादन लगभग 61,754 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) था जबकि सीवेज उपचार क्षमता लगभग 22,963 (MLD) था। जिसमें से 38,791(MLD) सीवेज (62 प्रतिशत) अनुपचारित रह जाता था।

- 2016 में दुनिया में 44.7 मिलियन मीट्रिक टन ई–कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें से केवल 20 प्रतिशत का पुनर्नवीनीकरण किया गया।

- प्लास्टिक का उत्पादन 1960 के दशक में 15 मिलियन टन से बढ़कर 2014 में 311 मिलियन टन हो गया और यह 2050 तक तीन गुना होने की उम्मीद है।

- भारत की आबादी, वैश्विक आबादी की लगभग 18 प्रतिशत है जबकि वैश्विक नवीकरणीय जल संसाधनों का सिर्फ 4 प्रतिशत भारत में उपलब्ध है।

- भारत में BUR 2 के अनुसार, 2014 में भारत का उत्सर्जन (भूमि उपयोग LULUCF के बिना) 2,607 $MtCO_2e$ हो गया जो कि 2010 में 2136.8 $MtCO_2e$ था

देश में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किये जा रहे कुछ प्रमुख कार्य

- पिछले पाँच वर्षों (2014–2019) के दौरान, भारत की अक्षय उर्जा क्षमता 34 GW से बढ़कर 83.38 GW हो गई है, जिसमें रिकार्ड 145 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- नवंबर 2019 तक 360 मिलियन से अधिक एल. ई. डी. बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष लगभग 47 बिलियन KWh ऊर्जा की बचत तथा प्रति वर्ष 38 $MtCO_2e$ उत्सर्जन में कमी आई है।

- भारत के राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) 2019 के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 712,249 वर्ग कि. मी. (भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 प्रतिशत) है जिसमें 2017 के अनुसार 708,273 वर्ग कि.मी. (21.57 प्रतिशत) से वृद्धि हुई है।

- भारत की सौर स्थापित क्षमता में 06 वर्षों में 13.5 गुना वृद्धि हुई है जो मार्च 2014 में 2.63 GW से बढ़कर नवंबर 2020 में 36 GW हो गई है।

- बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर–जीवाश्म स्त्रोतों की हिस्सेदारी मार्च 2015 में 30.5 प्रतिशत थी जो बढ़कर नवंबर 2020 में लगभग 38 प्रतिशत हो गई है।

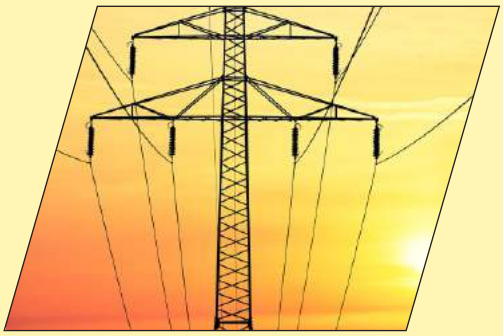

जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित ''इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल'' एकल बिंदु सूचना स्रोत का शुभारंभ

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर ने ''इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल'' का शुभारंभ दिनांक 27/11/2020 को किया।

वेब पोर्टल के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, श्री जावडेकर ने कहा कि यह पोर्टल ''एकल बिंदु सूचना संसाधन'' होगा, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये गये विभिन्न जलवायु संबंधी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ता इन पहलों की अद्यतन स्थिति का लाभ उठा सकें।

यह पोर्टल क्षेत्रवार अनुकूलन और शमन के उन कदमों को इंगित करता है, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एक स्थान पर अद्यतन जानकारी सहित उनके कार्यान्वयन के लिए उठाया जा रहा है। यह नॉलेज पोर्टल नागरिकों के बीच सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों, स्तरों पर उठाये जा रहे सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने में मदद करेगा।

इस नॉलेज पोर्टल में शामिल आठ प्रमुख घटक हैं, भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क, भारत का एनडीसी लक्ष्य, अनुकूलन संबंधी कार्रवाई, शमन संबंधी कार्रवाई, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीयजलवायु वार्ता, रिपोर्ट और प्रकाशन।

जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम ने सरकार और निजी क्षेत्र के बीच दीर्घकालिक एवं टिकाऊ साझेदारी कायम की

जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम ने सरकार और निजी क्षेत्र के बीच 05/11/2020 को दीर्घकालिक एवं टिकाऊ साझेदारी कायम की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि भारत पेरिस समझौते पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है और देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) पर काम कर रहा है। श्री जावडेकर ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जो 2 डिग्री के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं जो हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है

जलवायु परिवर्तन विषय पर वर्चुअल भारत सीईओ फोरम में उद्योगजगत की 24 अग्रणी हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक घोषणा जारी करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा यह घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है।

फोरम को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने उद्योगजगत को सुझाव दिया कि वे इसे लागू करें और सरकार को बताएं कि वे क्या कदम और पहल कर रहे हैं जो कि कार्बन से मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए सरकार को प्रदूषणकारी गतिविधियों के बारे में बताएं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से वित्तीय और तकनीकी सहायता पर हमारे आग्रह के बारे में एक ही स्थान पर होना चाहिए ताकि भारत भी आगे का रास्ता तय कर सके।

सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए उच्च–स्तरीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया

जलवायु परिवर्तन पर 'वॉक द टॉक' पर भारत की गंभीरता की पुष्टि करने वाले एक अन्य कदम में, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के सचिव की अध्यक्षता में पेरिस समझौते (एआईपीए) के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च–स्तरीय अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

एआईपीए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया पैदा करना है, जो सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अगसर है।

चौदह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, एआईपीए के सदस्य के रूप में काम करेंगे जो भारत के एनडीसी के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करेंगे और पेरिस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलवायु लक्ष्यों की निगरानी, समीक्षा और पुनरीक्षण करने के लिए समय–समय पर अपडेट जानकारी प्राप्त करेंगे।

एआईपीए का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करना होगा, पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, कार्बन मूल्य निर्धारण, बाजार तंत्र पर दिशानिर्देश जारी करना और अन्य समान उपकरण जिनका जलवायु परिवर्तन और एनडीसी पर असर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ–साथ बहु / द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान पर ध्यान देगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके जलवायु कार्यों को संरेखित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

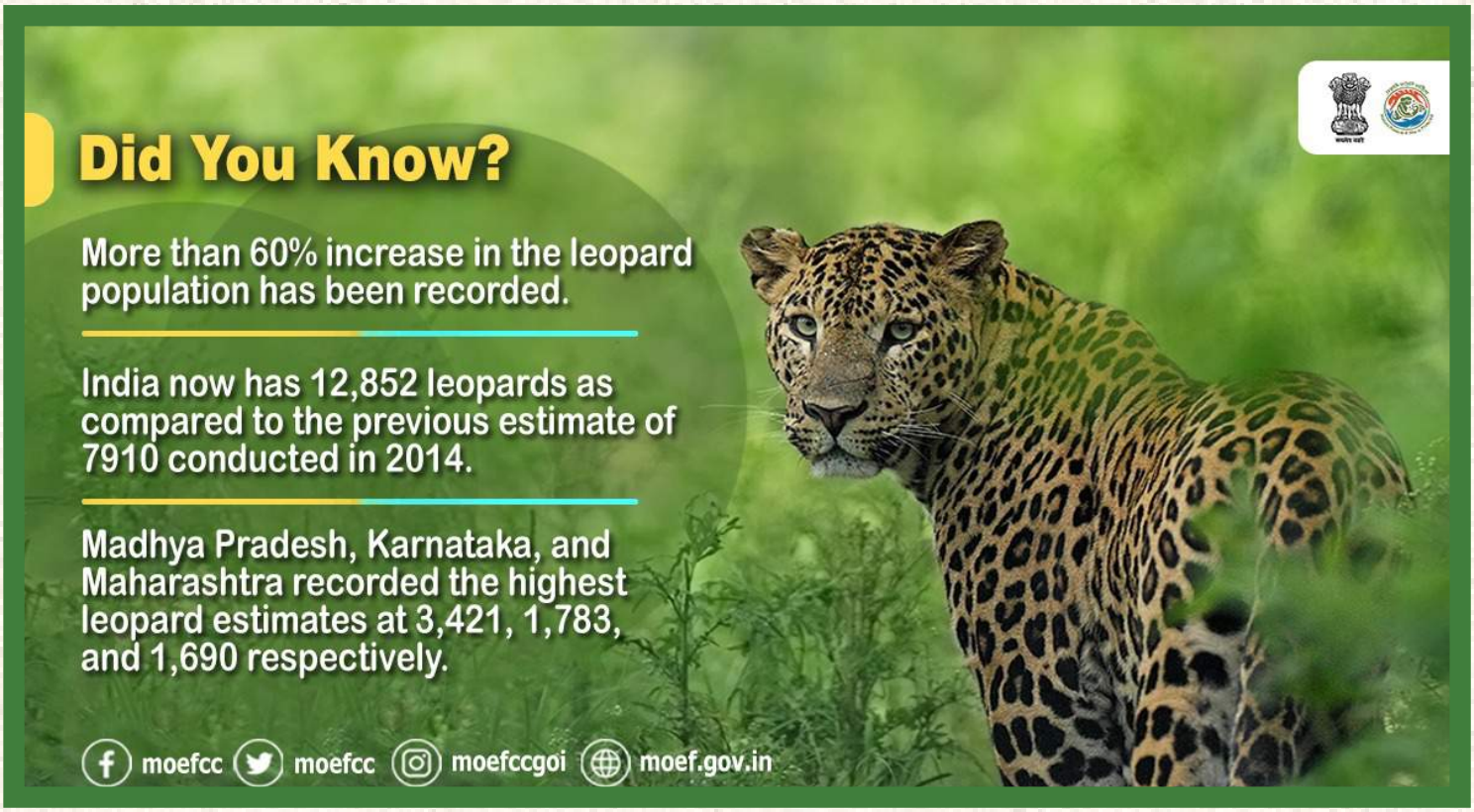

समाचार शीर्षक

बदलाव वन अर्थ जर्नल में इंसान की प्रजातियों पर जारी हुआ अध्ययन

जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गईं कई प्रजातियां

ZOOM रिपोर्टर
patrika.com

यह तो हम सभी जानते हैं कि होमा वंश में इंसान की बहुत सार प्रजातियां हैं और हम होमो सेपियन्स कहलाते हैं। हमें यह भी पता है कि समय के साथ इंसान की प्रजातियां विलुप्त होती गईं और अब केवल होमो सेपियन्स ही बचे हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इंसान की बाकी सारी प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? वैज्ञानिक कई सालों से इस प्रश्न का हल खोज रहे हैं और अब उन्हें इसका जवाब मिल गया है। एक अध्ययन के अनुसार, इंसान की प्रजातियों के विलुप्त होने के पीछे जलवायु परि वर्तन जिम्मेदार है। यह अध्ययन वन अर्थ जर्नल में

बदलावों से नहीं बिठा पाए तालमेल

अध्ययन के अनुसार, तेजी से बदले तापमान ने इंसान की प्रजातियों को विलुप्त करने में अहम भूमिका निभाई। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा कि मानव की कई प्रजातियां इन बदलावों से तालमेल नहीं बिठा पाईं और विलुप्त हो गईं। दरअसल, अध्ययन कर रही टीम ने कई दौर में जलवायु परिवर्तनों की स्थितियों का आंकलन किया। उन्होंने अध्ययन में प्रजातियों के जीवाश्मों को भी शामिल किया था।

तकनीकी विकास भी नहीं आया काम

अध्ययन में कहा गया है कि प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने में तकनीकी विकास भी कुछ काम नहीं कर सका। आग और पत्थर के हथियारों के आविष्कार के कारण प्रजातियों का एक सामाजिक नेटवर्क बन गया। कपड़ों का उपयोग और जेनेटिक आदान-प्रदान भी इनके बीच हुआ।

आज के लिए खतरनाक संदेश

अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा कि इस अध्ययन में जो नतीजे सामने आए हैं, वे काफी चौंका देने वाले है। इसमें यह पता चला कि इंसान की कई प्रजातियों ने अपने आवास जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी विलुप्ति से पहले ही खो दिए थे।

India in top 10 performers on climate change index

Vishwa.Mohan@timesgroup.com

New Delhi: India remains in the top 10 for the second year in a row in the latest global Climate Change Performance Index (CCPI) released in Germany on Monday. The biggest current emitter of greenhouse gases (GHG) China figures at 33rd rank while the largest historical polluter, the USA, appears at the bottom of the list.

Though India slid one position down from ninth in 2019 to 10th this year, the country's journey towards climate protection has been consistent with it improving its ranking from 31st in 2014.

Globally none of the countries assessed for the annual CCPI report are, however, on the path to meet their Paris Agreement commitment of keeping global warming increase below 2 degree celsius by the end of the century and actually to make efforts to restrict it to 1.5 degree celsius rise.

The list is prepared by assessing performances of 57 countries and the EU (as a whole) in four categories — GHG emissions (40%), renewable energy (20%), energy use (20%) and climate policy (20%). These 57 countries and the EU collectively are responsible for about 90% of global GHG emissions.

The CCPI is developed by not-for-profit organisations Germanwatch and NewClimate Institute (Germany) together with the Climate Action Network (CAN International). The CCPI 2021, covering the year 2020, shows that only two G20 countries — the UK and India — are among the high rankers while six others — the USA, Saudi Arabia, Canada, Australia, South Korea and Russia (32nd) — are at the bottom of the index. It's the second time in a row that the USA is bringing up the rear, below Saudi Arabia.

The report, covering CCPI, shows that overall, GHG emissions have increased slightly, but are actually falling in more than half of the countries (32) surveyed.

Full report on www.toi.in

BUT SLIPS ONE POSITION

Climate Change Performance Index (CCPI) Ranking 2020

*No country performs well enough in all four categories to achieve perfect score on performance index

राजधानी में 11 साल में 5वीं बार दिसंबर गर्म

- 21 दिसंबर को ही तापमान 10.5 डिग्री रहा जो सबसे कम

मौसम रिपोर्टर | रायपुर

राजधानी में 11 साल में 5वीं बार दिसंबर सबसे ज्यादा गर्म रहा। इस साल 21 दिसंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से तीन डिग्री कम था। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा थे, जिनके असर से खाड़ी में सिस्टम बनते रहे और नमी आती रही। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में तापमान में ज्यादा कमी नहीं आई। जबकि पिछले 11 वर्षों में 6 बार ऐसा हुआ, जब दिसंबर में ही न्यूनतम पारा 9 डिग्री के आसपास या उससे भी नीचे चला गया। इस बार महीने की सबसे ठंडी रात 21 दिसंबर को थी, जब रायपुर में पारा 10 डिग्री तो था ही, शहर के आउटर यानी लाभांडी में 6.5 डिग्री तक उतर गया था। रिकार्ड किया गया है। जहां तक ठंडे दिसंबर का सवाल है, वर्षा 2010, 2011, 2012, 2014, 2018 व 2019 में दिसंबर की रातें ज्यादा सर्दी थीं, जबकि 2013, 2015, 2016, 2017 में तापमान 10.5 डिग्री से ऊपर रहा। नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान 15 डिग्री तक आने के बाद जम्मू-कश्मीर में पश्चिम विक्षोभ आ गया। इसके कारण उत्तर भारत से ठंडी हवा प्रदेश में नहीं आ पाई और ठंड रूक गई। 23 नवंबर को अरब सागर में गति तूफान आया था, लेकिन प्रदेश में इसका कोई असर नहीं था। 25 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में निवार महातूफान पुडुचेरी तट से टकराया था। इसके कारण राजधानी में हल्की बौछारें पड़ीं थीं। सरगुजा संभाग के कई स्थानों पर तेज बारिश हुई थी।

नए साल की सर्दी से 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा

नई दिल्ली | नए साल के स्वागत और जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में ठंड ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के लोगों को साल के पहले दिन जबरदस्त ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ा। दिल्ली में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये पिछले 15 साल में सबसे कम है। इससे पहले आठ जनवरी 2006 को शहर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार तक शीत लहर के आसार बने रहने का अनुमान जताया है। शेष पेज 10

सम्पादक मंडल

- श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (मुख्य संपादक)
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- श्री अभिनव अग्रहरी
- श्री राजेश टोप्पो

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ
अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19
नवा रायपुर, छत्तीसगढ
ईमेलः chhattisgarh.sccc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgclimatechange.com